लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्डस में

प्रदेश का गौरव बढ़ा

देश में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के उपयोग के मामले में प्रदेश शासन प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक उपयोग के लिए इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्डस में भी स्थान मिला है। प्रशासन को चुस्त, दुरूस्त व पारदर्शी बनाने के लिए मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के नये-नये अनुप्रयोगों को लगातार अपनाया जा रहा है। वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा इस श्रृंखला में नवीन व सफल कड़ी है। भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा मध्यप्रदेश में वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली अप्रैल2004 में मंत्रालय व संभागीय मुख्यालयों पर आरंभ की गई थी। द्वितीय चरण में इसका विस्तार करते हुए मध्य प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को इससे जोड़ दिया गया। अब तक प्रदेश में 51 वीडियो कान्फ्रेंसिंग केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले तीन वर्षो की अवधि में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली का लगभग 22,350 घंटे उपयोग किया जा चुका है। मई 2007 तक विभिन्न विभागों की 1031 विभागीय बैठक इस सुविधा का उपयोग करते हुए की जा चुकी हैं। यह एक अनोखा रिकॉर्ड है जिसका गौरव मध्यप्रदेश को प्राप्त हुआ है। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा फरवरी 2006 से नियमित रूप से माह के प्रथम मंगलवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई कर समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

मध्यप्रदेश वीडियो कांफ्रेंसिंग के उपयोग में सबसे आगे

इस कार्यक्रम को समाधान ऑनलाइन नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश भर से प्राप्त जनशिकायतों में से कुछ लंबित शिकायतों का चयन किया जाता है। इनके शिकायतकर्ता व जिला अधिकारी से मुख्यमंत्री सीधे संवाद कर शिकायत निवारण करते हैं।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग कर जिलों में चल रही विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय स्तर पर ऑनलाइन रूप से कर पाना संभव हो गया है। मध्यप्रदेश में प्रतिमाह विभिन्न विभागों की लगभग 35 ऑनलाइन बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती हैं। जिनमें राज्य मुख्यालय व जिला स्तर के अधिकारी भाग लेते है। इस प्रणाली का उपयोग स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, मछली पालन, शिक्षा, वन, लोकनिर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला बाल विकास, आदिम जाति कल्याण, कृषि, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय भी इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के उपयोग से राज्य स्तर पर अधिकारियों की निगरानी व नियंत्रण क्षमता बढ़ी है।इस प्रणाली से राज्य व जिला स्तर पर मौजूद अधिकारियों का सम्पर्क व संवाद बढ़ा है।

पहले विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के लिए बैठकें संभाग मुख्यालयों व राजधानी में आयोजित होती थीं। इस प्रणाली के आरंभ हो जाने के बाद से बैठकों में आने-जाने में लगने वाले समय व व्यय में काफी कमी आई है। प्रदेश के मुख्य सचिव भी नियमित रूप से संभागायुक्तों व जिलाधीशों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर प्रशासनिक व्यवस्था, मूलभूत सुविधा कार्यक्रम व विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। - **फीचर्स**